Need to curb increasing child marriages during the pandemic

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है। सभापति महोदय, कोरोना महासंकट के दौरान स्कूल बंद होने से देश के लगभग सभी राज्यों में बेटियों की पढ़ाई और उनके उज्ज्वल भविष्य पर प्रश्न चिह्न लग चुका है। इससे बड़ी समस्या यह है कि स्कूल के safety net से वंचित होने के कारण बेटियों के बाल विवाह की संख्या बढ़ती जा रही है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय हेल्पलाइन, चाइल्डलाइन 1098 में एक RTI लगाई गई थी और अप्रैल से अक्टूबर, 2020 के बीच बाल विवाह से जुड़ी 18,324 distressed calls आई थीं। इसी के साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना में 200 से अधिक बाल विवाह के प्रकरण एवं कर्णाटक में 188 प्रकरण सामने आए हैं। हर राज्य के लिए यह एक बड़ी मुसीबत है। मुझे खुशी है कि इनमें से कई राज्यों में समय पर हस्तक्षेप करने से विवाह रोक दिए गए थे। मेरा महिला और बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि -

1. बाल विवाह पर national data प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को तत्काल राज्यव्यापी मूल्यांकन करने के निर्देश जारी किए जाएं।
2. हमारे कानून और नियम के क्रियान्वयन का सख्ती से पालन किया जाए। बाल वधुओं की उचित counseling के लिए district child welfare committee को सक्रिय किया जाए, आंगनवाड़ीकर्मियों और NGOs के साथ मिलकर mission mode पर ही बाल वधू और उनके परिवार तक पहुंचा जाए, ताकि हम लोग इन बेटियों की स्कूल वापसी में सहयोग दे पाएं।
3. इसी के साथ स्कूल drop out रोकने के लिए एक blueprint बनाया जाए और बाल विवाह संबंधी जागरूकता के प्रयासों को scale up किया जाए।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूं।

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूं।

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI MAZIBULLA KHAN (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SPECIAL MENTIONS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have received 35 requests. So, try to adjust the time. Otherwise, it will be difficult. We have about nine Special Mentions which I permitted. Please lay your Special Mentions.

Demand to resolve issues affecting retired bank employees

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Hon. Chairman, Sir, banking sector is an important component in the progress of the nation. Bank employees are the backbone of such an important sector. Pension Scheme for bank employees was introduced in the year 1993 w.e.f 01.01.1986. Bank retirees' pension has not been updated even for a single time in the past. But there has been substantial increase in prices of essential commodities including the cost of medical treatment, medicines, etc. The Government had given sympathetic thought to the concerns of the bank retirees and their demand. Finally, it had given direction to IBA/SBI Chairman to carry out updation of pension for bank retirees.

The family pensioners were receiving very meager amount as family pension, that is, they are receiving only 15 per cent of the last pay received by the pensioner. Considering this and to bring it at par with other sectors, the Government and IBA agreed to increase the family pension to 30 per cent without any ceiling. This proposal is pending with the Government for its approval and then implementation. The same was brought to the notice of the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman. She had agreed to have a relook at the issue.